**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न संख्या-237**
**उत्तर देने की तारीख-09/03/2026**

**शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि**

†*237. **श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
**श्रीमती भारती पारधी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,39,289.48 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' संबंधी उच्चस्तरीय स्थायी समिति के गठन का उद्देश्य शैक्षणिक पाठ्यक्रम को सेवा क्षेत्र की उभरती मांगों के अनुरूप बनाकर कौशल अंतर को पाटना और भविष्य की नौकरियों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव का मूल्यांकन करना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गलियारों के समीप, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पांच 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप' स्थापित करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) "ऑरेंज इकोनॉमी" में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) के माध्यम से 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं; और
(ङ) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (बीजीएफ) के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक कन्या छात्रावास स्थापित करने का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

**उत्तर**
**शिक्षा मंत्री**
**(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ङ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

**शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे और श्रीमती भारती पारधी द्वारा दिनांक 09.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 237 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) से (ङ): केंद्रीय बजट 2026-27 में, शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 139289.48 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जो बजट अनुमान 2025-26 की तुलना में 8.27 प्रतिशत अधिक है। 2026-27 के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए बजट आवंटन 83562 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में 4990 करोड़ रुपये (6.35 प्रतिशत) की समग्र वृद्धि है। 2026-27 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए समग्र बजट आवंटन 55727.22 करोड़ रुपये है जो वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में 5649.27 करोड़ रुपये (11.28%) की समग्र वृद्धि है।

भारत को विश्व में अग्रणी देश बनाने के लिए, वर्ष 2047 तक 10% वैश्विक हिस्सेदारी हासिल करने के उद्देश्य से, विकास, रोजगार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए, उभरती प्रौद्योगिकियों—जिसमें एआई शामिल है—का नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर प्रभाव का आकलन करते हुए तथा उसके अनुरूप उपाय प्रस्तावित करने के लिए, केंद्रीय बजट 2026-27 ने एक उच्च-स्तरीय 'एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज' स्थायी समिति के गठन की घोषणा की है जो विकसित भारत के मुख्य प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी।

केंद्रीय बजट 2026-27 में राज्यों को सहयोग प्रदान कर चैलेंज रूट के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

एक परामर्शात्मक प्रक्रिया के माध्यम से योजना की विस्तृत संरचना को अंतिम रूप दी जाएँगी जिसमें इसके कार्यान्वयन मॉडल, प्रमुख घटक, प्राथमिकता वाले क्षेत्र और संस्थागत व्यवस्थापन शामिल हैं। व्यापक रूप से, प्रस्तावित विश्वविद्यालय टाउनशिप को विश्व-स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान अवसंरचना प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है जिसमें नवाचार और उद्भवन सुविधाएँ, उद्योग साझेदारियाँ तथा टिकाऊ शहरी सुविधाएँ शामिल होंगी।
स्थानों का चयन उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, संपर्क क्षमता, क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकताओं, उद्योग से जुड़ने की अंतर्निहित, संतुलित क्षेत्रीय विकास और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे कारकों पर निर्भर करेगा।

भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र बढ़ता हुआ उद्योग होने के साथ जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की अनुमानित आवश्यकता है, 2026-27 बजट की 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई को सहयोग प्रदान करने की घोषणा की गई है।

वीजीएफ/पूंजी के माध्यम से प्रत्येक जिले में 1 बालिका छात्रावास की स्थापना की बजट घोषणा का उद्देश्य एसटीईएम में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करना है क्योंकि उच्चतर शिक्षा एसटीईएम संस्थानों में लंबे समय तक अध्ययन और प्रयोगशाला कार्य,छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां पेश करता है।

*******